



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]
No. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2008

विषय : चीन जन. गण. और ताइवान से केबल टाइज के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना ।

सं. 14/10/2007-डीजीएडी.—यतः मै. श्योरलॉक प्लास्टिक्स प्रा. लि., मुम्बई ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. और ताइवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित केबल टाइज (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और इसलिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा ऐसी पाटित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, अतः प्राधिकारी आरोपित पाटित की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे वसूल किया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच शुरू करते हैं ।

2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद केबल टाइज हैं, जो एक अंतर्निहित गियर रैक और एक छोटे खुले केस के भीतर एक सिरे पर एक रैचेट, केबल/वायर बॉचिंग प्रणाली की एक मितव्ययी एवं परिवर्तनशील पद्धति आदि के साथ एक मजबूत नायलोन टेप होते हैं। केबल टाइज को कई नामों से जाना जाता है उदाहरण के लिए निर्मुक्त करने योग्य या न योग्य (पुनःप्रयोज्य) टैग्स, स्ट्रैप्स, जिप टाइज, टाइरैप, रैट बेल्ट आदि और इनका अलग-अलग उपभोक्ताओं की अपेक्षानुसार विभिन्न आकारों में उत्पादन एवं बिक्री की जाती है। केबल टाइज वनपीस मोल्डेड तंत्र हैं जिनमें बाँधने और स्वतः लॉकिंग यंत्र वाले धातु के काँटे या जटिल फान नहीं होते हैं। एक बार एक नॉन-रिलिजेबल केबल टाइज को बाँध दिए जाने पर इसके वापस खिंचे जाने पर इसके विपरीत होता है और इसे केवल अधिक कस कर ही बाँधा जा सकता है। केबल टाइज आमतौर पर एकल उपयोग वाले डिवाइसेज होते हैं, तथापि उपभोक्ता की माँग के अनुसार पुनःप्रयोज्य केबल टाइज का उत्पादन भी किया जाता है।

3 घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

याचिकाकर्ता मै. श्योरलॉक प्लास्टिक्स प्रा. लि., मुम्बई के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के चार और उत्पादक हैं, अर्थात् मै. माइक्रोसाइनस प्रोडक्ट्स, भावनगर; मै. नोवाफ्लेक्स मार्केटिंग प्रा. लि., कोलकाता; मै. ब्लैकबर्न एंड कंपनी प्रा. लि., 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल और मै. फ्ल्यूकोन इंटरप्राइजेज, मुम्बई। याचिकाकर्ता कंपनी ने दावा किया है कि उनका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। याचिका नियमों के अंतर्गत स्थिति की शर्त पूरी करती है और याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर “घरेलू उद्योग” हैं। याचक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच हेतु वर्तमान याचिका को दायर करने की स्थिति में है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनीय है। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इनकी विशेषताएं एक-दूसरे के समान हैं। आगे यह भी दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं ने दोनों वस्तुओं का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. और ताइवान हैं जिन्हें उसके बाद इस जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश कहा गया है।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के अनुसार अनुप्रयोज्यता लागत पर विचार करते हुए ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिए जाने का दावा किया है और तदनुसार, उसने प्रमुख कच्ची सामग्री (नाइलोन) तथा अन्य कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के अनुसार अन्य लागतों पर परिकलित सामान्य मूल्य का दावा किया है। सामान्य मूल्य का दावा कारखाना द्वार स्तर पर किया गया है।

7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तु के लिए कोई विशेष वर्गीकरण नहीं है और इसलिए निर्यात कीमत का निर्धारण गौण स्रोतों अर्थात् आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त सौदे- वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत का निर्धारण भी सीआईएफ कीमत तथा कारखाना द्वार निर्यात कीमत निकालने के लिए भाड़ा ऋण लागत, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा तथा कमीशन आदि के लिए कीमत समायोजन के विभिन्न घटकों को अपना कर किया गया है।

8. पाटन मार्जिन

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य उनकी निवल निर्यात कीमतों से बहुत अधिक है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ताओं ने भारत में उत्पादन एवं खपत के समग्र रूप में और उसकी तुलना में पाटित आयातों में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति, पर्याप्त कीमत कटौती, चीन जन. गण. एवं ताइवान के बाजार हिस्से में वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, लाभ में कमी, लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभ आदि के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं को हुई वास्तविक क्षति का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है। इसके अलावा, माल की क्षति के अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने आयातों में वृद्धि दर, पर्याप्त कीमत कटौती तथा पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं के आधार पर दावा किया है कि पाटित आयातों से माल की क्षति होने का खतरा है।

10. जांच की अवधि (पीओआई)

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2006 से जून, 2007 तक की है। तथापि, क्षति संबंधी जांच के लिए अवधि में अप्रैल, 2003- मार्च, 04; अप्रैल, 04- मार्च, 05; अप्रैल, 05- मार्च, 06 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके अपने-अपने दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध समझे जाने वाले, भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित विधि और पद्धति से समस्त सूचना प्रस्तुत कर सकें। वर्तमान जांच में भाग लेने की इच्छुक कोई अन्य पार्टी निम्नलिखित को लिख सकती है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 240

उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी जांच समबन्धी अपना अनुरोध नीचे दी गई निर्धारित समय- सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से कर सकती है।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए ताकि उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें सम्बोधित पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम 7 के अनुसार इच्छुक पार्टियों के लिए प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो उसके कारण दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी सूचना जुटाने से इंकार करती है, अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर अन्यथा आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करती है अथवा जांच में काफी बाधा डालती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2008

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning the imports of Cable Ties from China PR and Taiwan.

No. 14/10/2007-DGAD.—Whereas M/s. Surelock Plastics Pvt. Ltd, Mumbai have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), alleging dumping of Cable Ties (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and have therefore requested for initiation of an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject countries and levy of anti-dumping duty on such dumped subject goods.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present petition is Cable Ties.

Cable Ties are sturdy Nylon tape with an integrated gear rack on one end a ratchet within a small open case, an economical and versatile method of Cable/Wire bunching systems, etc. Cable Ties are known by several names e.g. non-releasable or releasable (reusable) tags, straps, zip ties, tie wrap, rat belt etc. and produced & sold in different sizes as per requirement of the customers to Customer. Cable Ties are a one piece molded mechanism with no metal barbs or cumbersome wedges having fastening & self locking device. Once a non-releasable Cable Tie is pulled through, it prevents from being pulled back allowing tighter pulling only. Cable ties are generally single use devices, however reusable Cable Ties are also produced according to the demand of the customers.

14-21108-2

3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Apart from the petitioner M/s. Surelock Plastics Pvt. Ltd. Mumbai there are four other producers of subject goods in India namely M/s. Microsign Prtducts, Bhavnagar, M/s. Novaflex Mktg. Pvt. Ltd. Kolkata M/s. Blackburn & Co. Pvt. Ltd. 24, Parganas(South) West Bengal\ and M/s. Flu-Con Enterprises, Mumbai. The Petitioner Company has claimed that their production constitutes a major proportion of the total Indian production. The petition satisfies the condition of standing under the Rules and the petitioner constitutes "Domestic Industry" within the meaning of the Rules. The applicant has the standing to file the present petition for anti-dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3) (a) of Anti-Dumping Rules.

4. LIKE ARTICLE

Petitioner has claimed that there is no significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported ones from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both are technically and commercially substitutable and hold close resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. For the purpose of present investigation, product under consideration produced by the petitioner is being treated as like article to one imported from the subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

5. COUNTRIES INVOLVED

The countries involved in the present investigations are China PR and Taiwan here in after referred to as subject countries for the purposes of this investigation.

6. NORMAL VALUE

The Petitioner has claimed normal value for Taiwan based on international prices of major raw material and considering utilities cost as per domestic industry's cost of production. The Petitioner has claimed China PR to be treated as non-market economy and accordingly claimed constructed normal value on international prices of major raw material (Nylon) and other raw materials & other costs as per domestic industry's cost of production. Normal value has been claimed at ex-factory level.

7. EXPORT PRICE

The petitioner has claimed that the subject goods do not have a dedicated classification and hence the export price has been determined based on the transaction wise data provided by secondary sources viz. IBIS. Net export price has also been determined from the CIF price and adopting various elements of price adjustments towards freight, credit cost, bank charges, inland freight, insurance and commission etc to arrive at ex-works export price.

8. DUMPING MARGIN

There are sufficient evidences that the normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than their net export prices prima-facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

9. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioners have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping in terms of increase in imports in absolute terms and relative to production & consumption in India, significant price undercutting, increase in market share of China PR and Taiwan, decline in the market share of the domestic industry, deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc. There is sufficient, prima-facie evidence of material injury being suffered by the petitioners, caused by dumped imports from subject countries.

Further, in addition to material injury, petitioner has claimed that the imports are causing threat of material injury from the dumped imports based on rate of increase in imports, significant price undercutting and significant unutilized capacities.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI):

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is April 2006-June 2007. The injury investigation period will however, cover the period April, 2003-March, 04; April, 2004-March, 05; April, 2005-March, 06 and Period of Investigation.

11. SUBMISSION OF INFORMATION:

The exporters in the subject countries and their Government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty (40) days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

13. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority